International Research Journal of Human Resources and Social Sciences
ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)
Impact Factor- 5.414, Volume 5, Issue 1, January 2018
Website- www.aarf.asia, Email : editor@aarf.asia , editoraarf@gmail.com

प्राथमिक शिक्षा के प्रति अभिभावको के दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन

वन्दना सिंह
शोधार्थी
बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल

डॉ. हेमन्त खन्डई
सतत शिक्षा विभाग
बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल

प्रस्तुत शोधकार्य में सीहोर जिले में प्राथमिक शिक्षा के प्रति अभिभावको के दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। इस हेतु तय किए गए उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। इसके माध्यम से प्रयोज्यों को प्रश्नावली देकर उनसे उत्तर प्राप्त किये गये हैं। प्रस्तुत शोधकार्य हेतु सीहोर जिले में स्थित विद्यालयों को लिया गया है, इन चयनित विद्यालयों में से कुल 100 विद्यार्थियों के पालकों का साधारण यादृच्छिक न्यादर्श विधि के अन्तर्गत लॉटरी विधि के द्वारा चयन किया गया। सांख्यिकी गणना एवं परीक्षण से स्पष्ट होता है कि शिक्षक वर्ग तथा अन्य सर्विस वर्ग के मध्य प्राथमिक शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नही पाया गया। व्यवसायी वर्ग तथा अन्य आय वर्ग के मध्य प्राथमिक शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया।

तथ्यात्मक पदः प्राथमिक शिक्षा, अभिभावक, दृष्टिकोण

प्रस्तावना

मनुष्य विधाता की अनमोल कृति है तथा यह प्रकृति के अन्य जीवों से विशिष्टता लिए है। इसकी विशिष्टता का प्रमुख कारण मानव की चिंतनशील, सृजनात्मक, जिज्ञासु व अन्वेषक प्रवृत्ति है जिसके कारण वह नित्य नए सृजन कार्यों में लगा रहता है। वास्तव में उसकी जन्मजात प्रवृत्ति पशु के समान होती है किन्तु समाज में रहकर शिक्षा के माध्यम से उसका सामाजीकरण होता है। वह अपने अनुभवों व स्वविवेक से ज्ञान करता है। ज्ञान का प्रमुख आधार

© Associated Asia Research Foundation (AARF)
A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International e-Journal - Included in the International Serial Directories.

वास्तविक तथ्यों और सिद्धांतों से परिचित होना है। मनुष्य में विभिन्न तथ्यों को ज्ञात करने की जिज्ञासा होती है और इसी जिज्ञासा के फलस्वरूप वह अपने ज्ञान को बढ़ाता है। जैसे–जैसे ज्ञान की मात्रा बढ़ती जाती है वह उसे सुनियोजित करने का प्रयास करता है ओर यही प्रयास अनुसंधान का रूप ले लेता है। व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान को प्रामाणिकता प्रदान करने हेतु अनुसंधान करता है तथा इन अनुसंधानों के निष्कर्ष ही समाज के लिए उपयोगी होते हैं प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवनकाल में समुदाय में रहता है और इस हेतु वह समाज से अपेक्षा रखता है कि उसे अपने समुदाय से सरंक्षण प्राप्त हो अतः वह जिस समाज का हिस्सा होता है उसके मूल्य वांछनीय, महत्वपूर्ण और आदरपूर्ण होने चाहिए।

वर्तमान समय में हमारा देश मूल्यों के संकट के दौर से गुजर रहा है। आज भौतिकता अपने पैर पसारे है जिसके परिणामस्वरूप मूल्य संकुचित अवस्था में रह गए है। भारत देश अपनी सभ्यता व संस्कृति के लिए सदियों से विश्व में जाना जाता है और इसका श्रेय उन विभिन्न मूल्यों को ही जाता है जिन्होंने उसे अक्षुण्ण बनाए रखा है। विभिन्न शिक्षाशास्त्री व मनीषी सदैव से ही मानव कल्याण हेतु अथक प्रयास करते आए हैं और मानव कल्याण हेतु जीवन मूल्यों का विशेष महत्व है। जब भी देश व समाज में मूल्यों का महत्व घटा है सभ्यता व संस्कृति का पतन ही हुआ है।

किसी भी राष्ट्र की प्रगति का मापदण्ड उस देश की शिक्षा व्यवस्था के स्वरूप एवं स्थिति को माना जाता है। इसी दृष्टिकोण के अनुसार किसी भी राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था में प्राथमिक शिक्षा अपना विशिष्ट स्थान रखती है क्योंकि यही शिक्षा की प्रथम सीढ़ी होने के नाते राष्ट्र की भावी उच्च शिक्षा की पृष्ठभूमि का निर्माण करती है। राष्ट्रीय जीवन से निरक्षरता का प्रजातंत्र के निर्माण के लिये प्रगतिशील मार्ग प्रशस्त करने के उददेश्य से भारतीय संविधान के निर्माताओं ने भारतीय संविधान की धारा 45 में संवैधानिक निर्देशो का इस प्रकार से प्रतिपादन किया है। ''राज्य इस संविधान के क्रियान्वित किये जाने के समय से दस वर्ष के अंतर्गत जब तक कि सभी बालक 14 वर्ष की आयु पूर्ण नही कर लेगें, निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।'' इस संवैधानिक निर्देश के प्रतिरोपण से स्पष्ट होता है कि इसका मूल उददेश्य शिक्षा को सार्वभौम बनाना था।

लेकिन संविधान के लागू होने के 10 साल तक भी भारत अनेक सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं के चलते अपने सभी 6–14 साल तक के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध

करवाने में असमर्थ रहा। जिसके चलते यह समय सीमा समय–समय पर बढाई जाती रही। संवैधानिक रूप से भारत सरकार शिक्षा को मूलभूत अधिकार के रूप में (अनुच्छेद 21 (ए) संविधान के 86 वे संशोधन में दिसम्बर 2002 में जोडा गया एवं संसद द्वारा जुलाई 2009 में पारित किया गया) स्वीकार कर 6–14 साल के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त एंव अनिवार्य शिक्षा देने के लिये बचनबद्ध हैं।

इस उददेश्य की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने कई प्रयास किये जिनमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड (1986), नॉन फार्मल एजूकेशन स्कीम (1986), शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट (1987), लोक जुम्बीश (1992), जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (1994), मध्यान्ह भोजन योजना (1995), स्कूल चलो अभियान (1996) एवं सर्व शिक्षा अभियान (2001) प्रमुख हैं। अधिक आबादी, अनेक सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं एवं क्षेत्रीय विभिन्नता के चलते, इस विस्तृत स्तर पर शिक्षा प्रदान करना कठिन कार्य है। शर्मा (1996) के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा संबंधी कार्यों में मात्रा और सामाजिक महत्व की दृष्टि से वृद्धि हुई है, लेकिन उनकी उपलब्धि के लिये प्रावधानों में अनुपातिक रूप से वृद्धि नही हुई है। शैक्षिक योजनाओं का लाभ निम्न स्तरों तक पहुँचानें, योजनाओं का सही रूप से कार्यन्वित होने, सरकारी खजाने के सही उपयोग, स्थानीय निकायों का सरकारी निकायों के साथ मिलकर कार्य करने तथा इन योजनाओं का मूल्यांकन, संचालन, रखरखाब आदि करने की दृष्टि से शैक्षिक प्रशासन का कार्य जटिल हुआ है।

इस जटिलता को दूर करने के लिये भारत सरकार ने स्थानीय निकायों, जन समूह एवं जनता की सरकारी कार्यों मे भागीदारी को सुनिश्चित करने हेतु संविधान में 73 वाँ एंव 74 वाँ संशोधन किया संविधान के 73 वाँ संशोधन (1982) के अनुसार स्थानीय पंचायतों के निर्माण एवं पंचायतों का गाँव (ग्रामीण) स्तर पर संघीय कार्यों में सामाजिक भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है। 74 वाँ संशोधन में शहरों में नगर पालिका का निर्माण भी इसी उद्देश्य के लिये किया गया है। राज्यों से अपेक्षा की गई है कि वह इन स्थानीय निकायों के साथ मिलकर इन्हें अधिकार, कर्तव्य एवं वित्तीय संबंधी हस्तक्षेप करने की भागीदारी सुनिश्चित करें। इसी से भारत में शिक्षा के विकेन्द्रीकरण की शुरूआत मानी गयी।

सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ऐ.) की सफलता हेतू सरकार ने पहले से ही शिक्षा में समुदाय की भागीदारी पर बल दिया है। इसके फलस्वरूप राज्य, जिला, ब्लॉक, तहसील एवं ग्राम स्तर पर प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अधिकारों एवं कर्तव्यों का विकेन्द्रीकरण कर सामुदायिक

भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है। ग्राम स्तर पर विद्यालय के प्रमुख फैसले लेने अमलीकरण करने एवं कार्य प्रणाली पर निगरानी करने हेतु स्थानीय निकायों ग्रामीण शिक्षा समिति (व्ही.ई.सी.), पालक शिक्षक संघ (टी.पी.ए.) स्कूल प्रशासन समिति (एस.एम.पी.), समितियों का निमार्ण सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ऐ.) के अंतर्गत किया गया है। प्रस्तुत शोध में इन्हीं स्थानीय निकायों की ओर से प्राथमिक शिक्षा क्रियान्विकरण करने और सफल बनाने में किये गये प्रयासों को वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

चूंकि शोधार्थी मध्यप्रदेश के एक जिले में निवास करता है और शिक्षा के क्षेत्र में कई वर्षों से संलग्न है अतः उसे प्राथमिक शिक्षा की जमीनी सच्चाई नजर आई और उसने इस विषय को अपने शोध हेतु चयन किया है, जिससे वह यह जान सके कि पालक शिक्षक संघ एवं समाज के प्रबुद्धजन शिक्षा के प्रति अपनी क्या अभिवृत्ति रखते हैं, साथ ही चल रही सरकारी योजनाओं एवं उनके वास्तविक परिणामों को समाज के सामने रख सके। जिससे प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में कोई अवरोध उत्पन्न नही हो और वह निरन्तर अपने लक्ष्य प्राप्ति की और बढ़ सके।

किसी भी शोध की संकल्पना के लिये पूर्व शोधों का अध्ययन करना आवश्यक होता है। प्रस्तुत शोध की संकल्पना निम्न पूर्व शोधों के अध्ययन के आधार पर की गई है। **मेनन (1999)** ने हरियाणा राज्य के चार प्रमुख जिलों – हिसार, जींद, कैथल और सिरसा की ग्रामीण शिक्षा समितियों का अध्ययन जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत किया। शोध के प्रमुख निष्कर्षो में से ग्रामीण शिक्षा समिति के मानकों का सही ढंग से पालन न होना, महिला सदस्यों का उदासीन रवैया एवं महिला सदस्यों का तयशुदा आरक्षण (50 प्रतिशत) से भी कम होना प्रमुख थे। **फरेनकोईस (2002)** ने पेरिस विश्वविद्यालय तथा सेंटर ऑफ सांईसेस व हयूमेनिटिस नई दिल्ली के सौजन्य से Impact of the Educational Reform on the School Education System: The Field of Educational Gurantee Scheme (EGS) and other primary School in Madhya Pradesh नामक शोध किया, जिसके मुख्य उद्देश्य मध्यप्रदेश के शाहपुर एवं तोटक खुर्द नामक ब्लॉकों में शैक्षिक सुधारों के वैचारिक प्रसार एवं व्यवहारिक उपयोग की बात उभर कर सामने आयी। शोध में सरकारी तंत्र की निष्क्रियता को भी शिक्षा गारंटी योजना के सफल होने की राह का प्रमुख अवरोध बताया गया है।

सांख्यकीय विश्लेषण :–

संकलित न्यादर्श का सारणीकरण करके आवश्यकतानुसार मध्यमान, मानक विचलन एवं अन्य आवश्यक सांख्यिकी गणना एवं परीक्षण का उपयोग किया गया।

न्यादर्श

इस शोधकार्य में सीहोर जिले में प्राथमिक शिक्षा के प्रति पालकों की अभिवृत्ति का अध्ययन किया गया है। इस हेतु तय किए गए उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। इसके माध्यम से प्रयोज्यों को प्रश्नावली देकर उनसे उत्तर प्राप्त किये गये हैं। प्रस्तुत शोधकार्य हेतु सीहोर जिले में स्थित विद्यालयों को लिया गया है, इन चयनित विद्यालयों में से कुल 100 विद्यार्थियों के पालकों का साधारण यादृच्छिक न्यादर्श विधि के अन्तर्गत लॉटरी विधि के द्वारा चयन किया गया ।

शोध की परिकल्पनाएं :–

1. शिक्षक वर्ग तथा अन्य सर्विस वर्ग का प्राथमिक शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नही पाया जाता है।
2. व्यवसायी वर्ग तथा अन्य आय वर्ग का प्राथमिक शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नही पाया जाता है।

परिणामों की व्याख्या :–

तलिका – 01

शिक्षक वर्ग तथा अन्य सर्विस वर्ग का प्राथमिक शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण संबंधी तुलनात्मक परिणाम

समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	'टी' मूल्य	सार्थकता का मान	
					0.05	0.01
शिक्षक वर्ग	25	21.80	3.20	0.98	2.01	2.63
अन्य सर्विस वर्ग	25	20.80	4.06			

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि शिक्षक वर्ग तथा अन्य सर्विस वर्ग के मध्य प्राथमिक शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नही पाया गया। अतः परिकल्पना क्रमांक 01 सत्य सिद्ध होती है।

तलिका – 02

व्यवसायी वर्ग तथा अन्य आय वर्ग का प्राथमिक शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण संबंधी तुलनात्मक परिणाम

समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	'टी' मूल्य	सार्थकर्ता का मान	
					0.05	0.01
व्यवसायी वर्ग	25	21.00	5.29	0.55	2.01	2.63
अन्य आय वर्ग	25	20.80	4.99			

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि व्यवसायी वर्ग तथा अन्य आय वर्ग के मध्य प्राथमिक शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नही पाया गया। अतः परिकल्पना क्रमांक 02 सत्य सिद्ध होती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची –

भारत सरकार (2006), सर्व शिक्षा अभियान, अधिसूचना 2004 व 2005 नई दिल्ली भारत सरकार

भट्ट, ए. (2002) लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण एंव जनजातीय नेतृत्व, रावत पब्लीकेशन, नई दिल्ली

अग्रवाल, जे.सी. (2012) : उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षा, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा

आलोक, टी.डी.एस. (2003) : सांस्कृतिक पत्रकारिता, हरियाणा साहित्य अकादमी, पंचकूला

आनन्द, रचना (2013/2014) : किशोरावस्था एवं युवा, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा

अस्थाना, विपिन (1999) : मनोविज्ञान एवं शिक्षा में मूल्याकंन, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा, नवीनतम् संस्करण

अस्थाना, विपिन, श्रीवास्तव विजया, अस्थाना निधि (2013) : शैक्षिक अनुसंधान एवं सांख्यिकी, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा

भटनागर, आर.पी. (1995) : शिक्षा अनुसंधान : विधि एवं विश्लेषण, ईगल बुक्स इंटरनेशनल, मेरठ

गुप्ता, एस.पी. (2005) : सांख्यिकीय विधियाँ, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद

जैन, पायल भोला (2013) : मूल्य पर्यावरण तथा मानवधिकारों की शिक्षा अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा

कपिल. एच.के. (2008) : सांख्यिकीय के मूल तत्व, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा–7

कुप्पुस्वामी. बी. (1990) : बाल–व्यवहार और विकास, कोणार्क पब्लिशर्स प्रा. लि. दिल्ली

मुकर्जी, रवीन्द्रनाथ (2012) : सामाजिक शोध व सांख्यिकी, विवेक प्रकाशन जवाहर नगर, दिल्ली–7

पाण्डेय, रामशकल एवं मित्र करूणाशंकर (2008) : मूल्य शिक्षण, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा 7

पंड्या, शकुन्तला (2014) : विद्यालयों में नैतिक शिक्षा के प्रेरक विधाएँ, राजस्थान प्रकाशन, जयपुर

रत्तू, कृष्ण कुमार (2000) : दूरदर्शन हिन्दी के प्रयोजनमूलक विविध प्रयोग, इनो श्री पब्लिशर्स, जयपुर

रूहेला, सत्यापाल एवं भार्गव, महेश (2012) : उभरते भारत में शिक्षा, एच.पी. भार्गव बुक हाउस, आगरा – 4

सरीन, शशिकला एवं सरीन, अंजनी (2007) शैक्षिक अनुसंधान विधियाँ, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा

सक्सेना, एन.आर. स्वरूप एवं चतुर्वेदी, शिखा (2007) उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, आर. लाल बुक डिपो, मेरठ, पृष्ठ क्रमांक 163, 164

शर्मा, पी.डी. (2016) : भारत में शिक्षा स्तर, समस्याएँ एवं मुद्दे, श्री विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा

शर्मा, आर.ए. (1998) : शिक्षा अनुसंधान, सूर्या पब्लिकेशन, निकट गवर्नमेन्ट कॉलेज, मेरठ, नवीन संस्करण, पृष्ठ क्रमांक 94, 95

शर्मा, आर.के. एवं दुबे, एस.के. : मूल्यों का शिक्षण, राधा प्रकाश मन्दिर प्रा.लि., आगरा

शर्मा, आर.के., बरौलिया, ए., शर्मा एच.एस., एवं तिवारी, मूल्य शिक्षा एवं मानवाधिकार, राधा प्रकाश मन्दिर प्रा.लि., आगरा

श्रीवास्तव, डी.एन. (2007/2008) : सांख्यिकी एवं मापन, अग्रवाल पब्लिकेशन आगरा–7

श्रीवास्तव, मेघा (2008–09) "विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर का नैतिक मूल्यों पर पड़ने वाले प्रभाव का एक अध्ययन", देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (लघु शोध प्रबन्ध)

श्रीवास्तव. पी, (2017) "निचली बस्ती के किशोरों के मध्य नैतिक निर्णय", बिहेवियरल साइंटिस्ट (बाइ–एनुअल), वाल्यूम 18, नं 2, पृ. क्र. 131–136

सिंह, अरूण कुमार (2012) : उच्चतर सामान्य मनोविज्ञान, मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशन, दिल्ली

सिंह, रामपाल एवं शर्मा, ओ.पी. (2008) : शैक्षिक अनुसंधान एवं सांख्यिकी, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा–7

सोनी, रामगोपाल (2012) : उदयोन्मुख भारतीय समाज में शिक्षक, एच.पी. भार्गव बुक हाउस, आगरा

वजाहत, असगर एवं रंजन, प्रभात (2014) : टेलीविजन लेखन, राधाकृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, दरियागंज नई दिल्ली।

Aggarwal, J.C. (2011) : Theory And Principles of Educaiton, Vikas Publishing House Pvt. Ltd. Noida.

Buch, M.b. (1983-88) : Fourth Survey of Research in Education, National Council of Education Research and Training, New Delhi, Vol. I

Buch, M.b. (1983-88) : Fourth Survey of Research in Education, National Council of Education Research and Training, New Delhi, Vol. II

Buch, M.B. (1998-92) : Fifth Survey of Research in Education, National Council of Education Research and Training, New Delhi. Vol.-I

Buch, M.B. (1998-92) : Fifth Survey of Research in Education, National Council of Education Research and Training, New Delhi. Vol.-II

Deka T. (2003) Panchayati Raj for developing Rural India, Retrieved from www.Edcuationforallindia.com Page 44

Francois, L (2012) Impact of the Educational Reform on school system. The field study of EGS and other primary school in Madhya Pradesh, New Delhi. French Research Institute of India.

Garrett, Henry E. (2007) : Statistic in Psychology and Education, Paragon International Publisher, New Delhi, Twelth Indian Reprint